RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2016-2018 IPT indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 03 OCTOBER TO 09 OCTOBER 2018 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 04 ■ अंक 06 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

कच्चे तेल का भाव अगर हुआ 100 डॉलर तो दुनिया पर होगा ये असर

Page 2

जीएसटी कलेक्शन नवंबर-दिसंबर में एक लाख करोड़ रुपये के पार जाने की उम्मीद

Page 3

कृषि जनगणना के आंकड़े जारी: कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी

Page 7

editoria!

सौर ऊर्जा की चमक

देश के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैन्युएल मैक्रों के साथ संयुक्त रूप से 'चैंपियंस आफ द अर्थ अवॉर्ड' देने की घोषणा की गई है। यूनाइटेड नेशंस की ओर से पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा सम्मान है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन तथा पर्यावरणीय कार्रवाई की दिशा में नई पहलकदमियों को प्रोत्साहन देने के लिए मोदी और मैक्रों को यह सम्मान मिला है। ये दोनों राजनेता दुनिया के उन छह प्रबुद्ध लोगों में हैं, जिन्हें पर्यावरण में बदलाव की कोशिशों के लिए पुरस्कार हेतु चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की पहल है, जिसे भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से नवंबर 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन सीओपी-21 के इतर शुरू किया था। आईएसए एक संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो सौर ऊर्जा संपन्न देशों के साथ गठजोड़ में इसको प्रोत्साहन देने के लिए काम करता है। भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तेजी से तरक्की की है, वह पूरे विश्व के लिए सुखद आश्चर्य का विषय है। बीते तीन साल में भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन अपनी स्थापित क्षमता से चार गुना बढ़ कर 10 हजार मेगावाट की सीमा पार कर गया है। इस क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए विदेशी कंपनियों की निगाहें भी भारत पर टिकी हुई हैं और वे लगातार इसमें निवेश कर रही हैं। मरकॉम कम्युनिकेशंस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2017 में सौर ऊर्जा के मामले में तीसरे सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरा है और इस मामले में सिर्फ चीन और अमेरिका से पीछे है। रिपोर्ट के अनुसार 2017 में भारत ने रेकॉर्ड 9600 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं लगाईं, जो 2016 में 4300 मेगावाट के मुकाबले दोगुने से भी अधिक है। आईएचएस मार्किट का अनुमान है कि भारत 2018 में, यानी इसी साल अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ जाएगा। उसका कहना है कि इस साल भारत 11 गीगावाट तक की परियोजनाएं लगाएगा जबकि अमेरिका 10 गीगावाट तक के ही प्रॉजेक्ट्स लगाएगा। हालांकि सौर ऊर्जा का क्षेत्र इतना चमकीला भी नहीं है। अभी सरकार सौर ऊर्जा उत्पादन पर भारी सब्सिडी दे रही है, जिससे इसमें उछाल है। लेकिन इसकी मार पारंपरिक बिजली परियोजनाओं पर पड़ रही है, जिनका कमजोर पड़ना बाद में हमारे लिए भारी पड़ सकता है। सरकार को देखना होगा कि सौर ऊर्जा को बढ़ाने के चक्कर में ताप बिजलीघरों की हालत कहीं और न बिगड़ जाए और निजी कंपनियां इनसे पल्ला न झाड़ने लगें। इसलिए देर-सबेर हमें सोलर एनर्जी को प्रतिस्पर्धी बनाना होगा और कोयले से चलने वाले अपने बिजलीघरों पर से प्रदूषणकारी उद्यम का कलंक हटाना होगा।

रुपया पहली बार पहुंचा 73 के पार

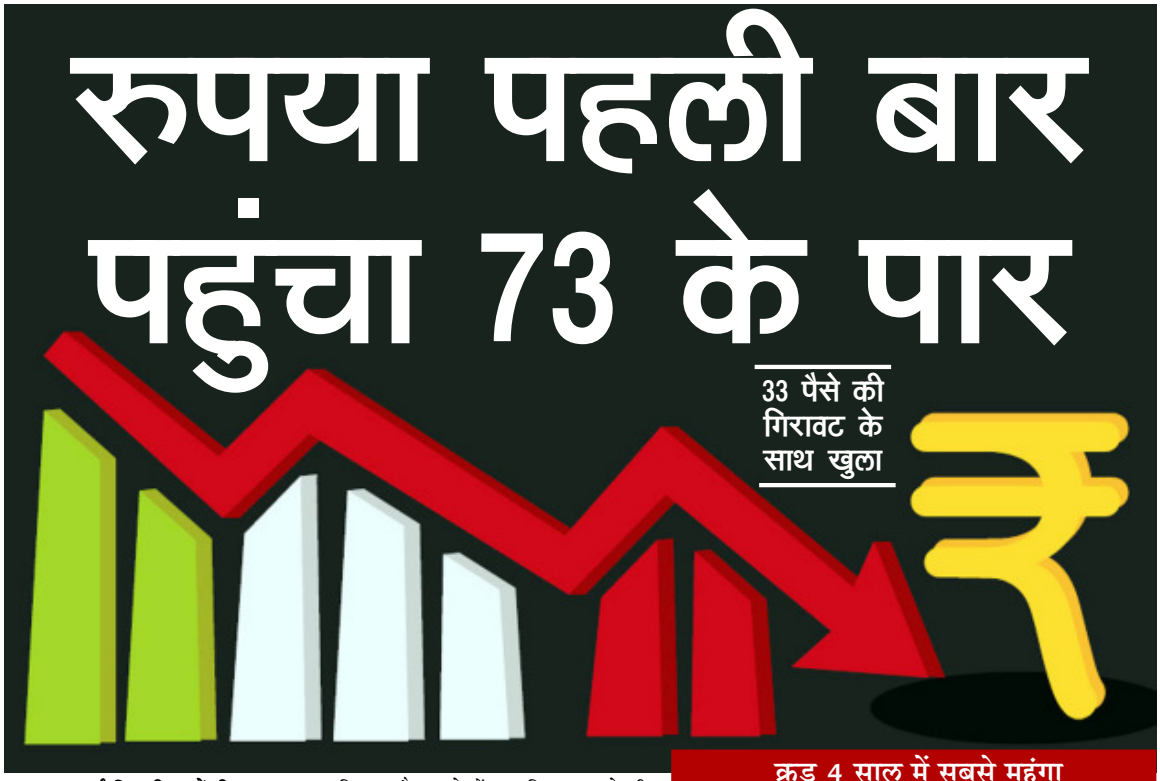

नई दिल्ली। एजेंसी

डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को रुपये ने पहली बार 73 का आंकड़ा पार कर लिया है.। एक डॉलर के मुकाबले रुपया 33 पैसे की गिरावट के साथ खुला है।

इस गिरावट के साथ शुरुआत करने के बाद रुपया 73.24 के स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले सोमवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 72.91 के स्तर पर बंद हुआ। यह पहली बार है जब रुपये में डॉलर के मुकाबले इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रुपये के अब तक के इतिहास में यह सबसे बड़ी गिरावट है। रुपये में यह गिरावट आगे भी बढ़ने की आशंका है। दरअसल यूएस की तरफ से ईरान पर सैंक्शन लगाए जाने का समय नजदीक आने से कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर उथल-पुथल शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर रुपये पर भी देखने को मिलेगा। बुधवार को कच्चे तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि यूएस की तरफ से ईरान पर लगाए जाने वाला सैंक्शन 4 नवंबर से प्रभावी हो जाएगा। विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं कि इस सैंक्शन के चलते कच्चे तेल की सप्लाई में कमी आ सकती है। दूसरी तरफ, बुधवार से शुरू हो रही भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक पर भी फॉरेक्स मार्केट की नजर है। इस मीटिंग में आरबीआई रुपये को सहारा देने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है।

क्रूड 4 साल में सबसे महंगा

■कच्चा तेल महंगा होने से रुपए पर दबाव बढ़ा। ब्रेंट क्रूड का रेट बुधवार को 84.94 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। नवंबर 2014 के बाद यह सबसे ज्यादा है। ■कारोबारियों के मुताबिक इंपोर्टर्स की ओर से डॉलर की मांग बढ़ने से रुपए की वैल्यू कम हुई। सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ने की भी आशंका बनी हुई है। ■शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली से भी रुपए में गिरावट आई। सोमवार को विदेशी निवेशकों ने 1,842 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।■ विश्लेषकों का कहना है कि ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू होने के बाद कच्चा तेल और महंगा होगा। इसका रुपए पर असर पड़ेगा। डॉलर के मुकाबले रुपया 74 के नीचे जा सकता है।

तेल खोज क्षेत्रों के लिये अनुबंध पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में पहली खुली क्षेत्र नीलामी (ओएएलपी-1) के तहत आबंटित 55 तेल एवं गैस खोज क्षेत्रों में 5,900 करोड़ रुपये निवेश की प्रतिबद्धता जतायी गयी है। खनन क्षेत्र के दिग्गज अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली कंपनी वेदांता लि. ने ओएएलपी-1 में पेश 55 तेल एवं गैस खोज ब्लाक में से 41 हासिल किये हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि इसको लेकर अनुबंध पर सोमवार को दस्तखत किये गये। सार्वजनिक क्षेत्र की आयल इंडिया लि. को नौ ब्लाक मिले जबकि आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) को केवल दो ब्लाक मिले। सार्वजनिक क्षेत्र की गेल तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. की तेल खोज एवं उत्पादन इकाई हिंदुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी (एचओईसी) को एक-एक ब्लाक मिला।

पेट्रोलियम सचिव एम एम कुट्टी ने कहा कि ओएएलपी के दूसरे दौर की नीलामी जल्दी ही शुरू होगी। इसमें 14 ब्लाक की पेशकश की जाएगी। उन्होंने कहा कि 14 ब्लाक में से चार महानदी बेसिन में है। इसे हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने चिन्हित किया है। प्रधान ने उत्पादन साझेदारी अनुबंध पर हस्ताक्षर के लिये आयोजित समारोह में कहा, "हमें 55 ओएएलपी-1 ब्लाक में 5,900 करोड़ रुपये से अधिक निवेश की प्रतिबद्धता प्राप्त हुई है।" इन 55 ब्लाक में 1.45 लाख करोड़ रुपये मूल्य का हाइड्रोकार्बन संसाधन होने का अनुमान है। भारत ने पिछले साल जुलाई में कंपनियों को अपनी रूचि के हिसाब से ब्लाक चुनने की अनुमति दी। इस पहल का मकसद देश में 28 लाख वर्ग किलोमीटर के वैसे क्षेत्र को खोज एवं उत्पादन के दायरे में लाना था जहां अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इस नीति के तहत कंपनियों को तेल एवं गैस संभावना वाले वैसे क्षेत्रों के लिये रूचि पत्र देने की अनुमति दी गयी जो उत्पादन एवं खोज लाइसेंस के अंतर्गत नहीं है।

कच्चे तेल का भाव अगर हुआ

डॉलर तो दुनिया पर होगा ये असर

नई दिल्ली। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कच्चे तेल के भाव में इस प्रकार की बढ़ोतरी को देखते हुए पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि साल 2014 के बाद एक बार फिर कच्चे तेल का भाव 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। ऐसे में यदि कच्चा तेल शतकीय आंकड़ा पार कर लेता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खासा असर देखने को मिल सकता है। तेल के भाव में तेजी से निर्यातक देशों को बंपर रिटर्न मिलने वाला है। इन देशों की तेल कंपनियों से लेकर सरकारी खजाने में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं, आयातक देशों के लिए तेल का ये खेल महंगा पड़ने वाला है। आयातक देशों में तेल के बढ़ते दाम से मुद्रास्फिति तो बढ़ेगी ही, साथ ही इन देशों में तेल डिमांड पर भी असर डालेगा। इसी बीच थोड़ी राहत की बात ये है कि ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के मुताबिक, साल 2011 के मुकाबले इस साल यानी 2018 में कच्चे तेल का भाव 100 डॉलर प्रति बैरल पर जाने से व्यापक असर देखने को नहीं मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अधिकतर अर्थव्यवस्थाएं अब एनर्जी पर कम निर्भर है।

वैश्विक ग्रोथ पर क्या पड़ेगा असर?

कच्चे तेल के भाव में इजाफे से हाउसहोल्ड इनकम प्रभावित होने के साथ-साथ उपभोक्ता खर्च भी कम हो जाएगा। चीन कच्चे तेल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है वहीं भारत तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। ऐसे में इन देशों की मुद्रास्फिति बढ़ने की आशंका है। वहीं, ठंड के मौसम आने के बाद उपभोक्ता दूसरे एनर्जी विकल्पों के तरफ आकर्षित होंगे जैसे बायोफ्यूल, प्राकृति गैस आदि। हालांकि अभी इसमें थोड़ा समय है। इन्डोनेशिया ने पहले ही बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है।

ईरान और ट्रम्प का बाजार पर कितना होगा असर?

कच्चे तेल को लेकर जियोपॉलिटिक्स अभी भी एक वाइल्ड कार्ड की तरह है। अमरीका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर अभी मध्य-पूर्वी देशों के निर्यात पर असर देखने को मिलेगा। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओपेक देशों पर तेल उत्पादन को लेकर दबाव बना रहे हैं। एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि वेनेजुएला, लिबीया और नाइजीरिया जैसे देशों में आर्थिक अस्थिरता से भी कच्चे तेल के उत्पादन को झटका लगा है। हालांकि वैश्विक रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैश ने अनुमान लगाया है कि कच्चे तेल का भाव 100 डॉलर प्रति बैरल के पार नहीं जा सकेगा हिकिसका होगा फायदा, किसे मिलेगी मातअधिकतर तेल उत्पादक देश दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। सउदी अरब इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर है जहां साल 2016 के मुताबिक तेल उत्पादन से होने वाली कमाई जीडीपी में 21 फीसदी की हिस्सेदारी रखती है। ये आकंड़ा रूस से दोगुना है जो कि दुनिया के 15 उभरते बाजारों में से एक है। नाइजीरिया और कोलम्बिया को भी इससे फायदा होने वाला है। कच्चे तेल से इकट्ठा होने वाले राजस्व से इन देशों को अपना बजट समेत राजकोषिय घाटा की भरपाई करने में भी मदद मिलेगी। वहीं भारत, चीन, ताइवान, चिली, तुर्की, इजिप्ट और यूक्रेन जैसे देशों में इससे नुकसान होगा। कच्चा तेल खरीदने के लिए इन देशों को पहले से अधिक खर्च करने होंगे जिससे इन देशों के चालू खाते पर भी असर देखने को मिलेगा।

दुनियाभर के देशों के मुद्रास्फिति पर क्या होगा असर?

आमतौर पर एनर्जी प्राइस का सीधा असर दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर देखने को मिलता है। ऐसे में नीति बनाने वाले लोगों के लिए भी चुनौती है। लेकिन तेल में लगातार बढ़ रहे इन दामों से मुद्रास्फिति में भी बढ़ोतरी होगी। यदि मुद्रास्फिति में तेजी आएगी तो केंद्रीय बैंकों को अपने मौद्रिक नीतियों में ढील बरतनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक कच्चे तेल के भाव को लेकर पहले से ही सतर्क हैं।

ओएनजीसी को आईओसी, गेल में अपनी हिस्सेदारी बेचने की जल्दी नहीं

नई दिल्ली। एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी को इंडियन ऑइल कॉरपोरेशन और गेल में अपनी हिस्सेदारी बेचने की कोई जल्दी नहीं है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम शेयरों की बिक्री के लिए सही कीमत मिलने का इंतजार करेंगे। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) की आईओसी में 13.77 प्रतिशत और गेल इंडिया में 4.86 फीसदी की हिस्सेदारी है। अधिकारी ने कहा, 'ये सच है कि अब हम पूरी तरह एकीकृत कंपनी हैं। हम देश के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक हैं। एचपीसीएल के अधिग्रहण से हमारी मौजूदगी का दायरा और व्यापक हुआ है। इसलिए ओएनजीसी के लिए इंडियन ऑइल कॉरपोरेशन की हिस्सेदारी रखने का कोई मतलब नही हैं। हालांकि, हम सही कीमत मिलने का इंतजार करेंगे।' उन्होने बताया कि वित्त वर्ष 2017-18 में ओएनजीसी को आईओसी तथा गेल में अपने निवेश पर करीब 3,000 करोड़ रुपये की लाभांश आय हुई है। अधिकारी ने कहा, 'यह अच्छी लाभांश आय है और इससे हमें शेयरों को लंबे समय तक अपने पास रखने में मदद मिलेगी। हमें शेयरों को बेचने की कोई जल्दी नहीं है। हम सही कीमत मिलने का इंतजार करेंगे।'

ओएनजीसी की आईओसी में 20,500 करोड़ रुपये से अधिक की 13.77 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यह कीमत मुंबई शेयर बाजार में सोमवार को कंपनी के शेयर मूल्य 153.80 रुपये प्रति शेयर के भाव पर है। इसी प्रकार गेल में कंपनी की 4,200 करोड़ रुपये की 4.86 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सोमवार को गेल का शेयर मूल्य 380.75 रुपये प्रति शेयर पर था। अधिकारी ने कहा, 'जनवरी में इंडियन आयल के शेयर का दाम 195 रुपये प्रति शेयर था जोकि अब 153- 154 रुपये प्रति शेयर पर चल रहा है। ऐसे में इतने घाटे पर शेयर बेचना बुद्धिमानी नहीं होगी।'

देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिये स्थिर मुद्रा जरूरी: सीआईआई

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने कहा कि रुपये में गिरावट आने का निर्यातकों को फायदा नहीं होता है, इसके बजाए, भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालिक टिकाऊ विकास के लिए स्थिर मुद्रा जरूरी है। चैंबर ने एक बयान में कहा कि मौजूदा वैश्वीकृत माहौल में कच्चा माल, माल परिवहन शुल्क, गोदाम और अन्य संबंधित सेवाओं जैसे अधिकांश खर्च विदेशी मुद्रा में या आयात समानता मूल्य पर अंकित होते हैं। इसके अलावा, अधिकांश निर्यातक आदेशों की बुकिंग करने के समय दीर्घावधि हेजिंग करते हैं, जबकि आयातक रुपये के मूल्यह्रास का हवाला देते हुए कीमतों में कमी लाने का दबाव डालते हैं। सीआईआई की निर्यात-आयात की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष संजय बुधिया ने कहा, 'इसलिए, यह वास्तविकता होने के बजाय एक धारणा ज्यादा है कि रुपए में गिरावट से निर्यातकों को मदद मिलती है। मौजूदा स्थिति में जरूरत है एक स्थिर मुद्रा की जो कीमतों को तय करने और आज के प्रतिस्पर्धी वैश्विक पर्यावरण में आर्डर स्वीकार करने के लिए स्थिरता और निश्चितता प्रदान करे।' भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी बढ़ाने के लिए 36,000 करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड खरीदने की योजना की घोषणा की है, इसके बावजूद सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 36 पैसे कमजोर होकर 72.84 रुपये रह गया। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले घरेलू मुद्रा रुपया 11 पैसे की तेजी के साथ एक सप्ताह के उच्च स्तर 72.48 प्रति डॉलर पर बंद हुई थी। हाल के सप्ताहों में, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और डॉलर के मजबूत होने के बीच रुपये में गिरावट रही। केंद्रीय बैंक रुपये में तेजी लाने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है।

जीएसटी कलेक्शन नवंबर-दिसंबर में एक लाख करोड़ रुपये के पार जाने की उम्मीद

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि नवंबर और दिसंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर जाएगा। त्योहारी मौसम की मांग और सरकार के कर अपवंचना रोधी उपायों से जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। सितंबर महीने में जीएसटी राजस्व बढ़कर 94,442 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। अधिकारियों का कहना है कि त्योहारी मौसम में मांग बढ़ने से यह आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपये को पार कर सकता है। एक अधिकारी ने कहा, 'मौजूदा रुख को देखते हुए उम्मीद है कि जीएसटी का मासिक कलेक्शन आंकड़ा नवंबर और दिसंबर के दौरान एक लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा। नवंबर और दिसंबर के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों में अक्टूबर और नवंबर में की गई खरीद बिक्री के आंकड़े दिखेंगे।

अधिकारी के अनुसार आमतौर पर लोग गणेश चतुर्थी तक अपनी खरीद टालते हैं। इससे त्योहारी मौसम की शुरुआत होती है। इसके अलावा राजस्व विभाग के कर अपवंचना रोकने के उपायों से राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी। लक्ष्मीकुमारन ऐंड श्रीधरन के भागीदार एल बद्री नारायण ने कहा, 'त्योहारी सीजन की मांग से जीएसटी कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपये को पार कर जाएगा। यह वह समय होता है जबकि लोग खरीदारी करते हैं और कंपनियां छूट और अन्य पेशकशें देती हैं। हमें उम्मीद है कि बिक्री बढ़ने से सरकार को ऊंचा राजस्व मिलेगा।' एएमआरजी ऐंड एसोसियेटस पार्टनर रजत मोहन ने भी कहा कि त्यौहारों और शादी-ब्याह का समय शुरू होने से कुल मिलाकर मांग बढेगी और जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने हालांकि त्यौहारी मौसम निकलने के बाद राजस्व में कमी की आशंका जताई है। उनके मुताबिक वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में खरीद- बिक्री सुस्त पड़ जाती है।

करेंसी संकट से बचाव के लिए आरबीआई करेगी 36,000 करोड़ रुपये का संचार

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

केन्द्रीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि वह अक्टूबर के दौरान मुद्रा बाजार में 360 बिलियन रुपये (4.95 बिलियन डॉलर) का संचार करेगा। आरबीआई का यह कदम मुद्रा बाजार में क्रेडिट की कमी के चलते उठाया जा रहा है। रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि इस संचार से उसे आगामी त्योहारों के दौरान बाजार में पर्याप्त मात्रा में करेंसी की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह कदम रिजर्व बैंक ने केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्ज में 700 बिलियन रुपये की कटौती करने के ऐलान के बाद जिसे साफ संकेत माना जा रहा है कि केन्द्रीय बैंक सरकारी बॉन्ड की बाईबैक के लिए तैयार है। इससे पहले 27 सितंबर को जारी प्रेस रिलीज के जरिए केन्द्रीय बैंक ने दावा किया था कि वह मुद्रा बाजार में जरूरत के मुताबिक तरलता रखने के लिए तैयार है। रिजर्व बैंक के मुताबिक अक्टूबर के दूसरे, तीसरे और चौथे हफ्ते के दौरान वह ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सरकारी बॉन्डों

की खरीदारी करेगा। हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा है कि सरकारी बॉन्ड खरीदने की उसकी निर्धारित सीमा को वह मुद्रा बाजार में तरलता को देखते हुए बदल भी सकता है।

गौरतलब है कि सोमवार को मुद्रा बाजार में भारत सरकार के बॉन्ड ईल्ड अपने एक महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। बाजार के जानकारों का मानना है कि सरकारी बॉन्ड के निवेशकों ने केन्द्र सरकार के कर्ज में कटौती के फैसले के चलते बॉन्ड में अपना डर जाहिर किया है। केन्द्र सरकार का बेंचमार्क 10 साल के बॉन्ड ईल्ड 12 बेसिस प्वाइंट की गिरावट के साथ 7.90 फीसदी पर रहा। बॉन्ड का यह स्तर 29 अगस्त के बाद का न्यूनतम स्तर है। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने नए कर्ज में 700 बिलियन रुपये की कटौती करने का फैसला स्माल सेविंग स्कीमों में उम्मीद से अधिक 750 बिलियन रुपये की कमाई के चलते लिया है।

डूब गया ये शैडो बैंक तो टूट जाएगा SBI और LIC का रूरल कनेक्ट

रिजर्व बैंक ने अक्टूबर में अतिरिक्त तरलता संचार के लिए मुद्रा बाजार में रुपये के लिए जारी चुनौतियों के चलते उठाया है। केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि संचार किए जाने वाले 350 बिलियन रुपये से त्यौहारों के दौरान बाजार में पर्याप्त मात्रा में करेंसी उपलब्ध रहेगी।

कैट ने कहा...

जीएसटी में आपदा कर लगाना ठीक नहीं

नई दिल्ली। व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में किसी तरह का उपकर या कर लगाने का सुझाव सही नहीं है और यह एक राष्ट्र -एक कर के सिद्धांत के खिलाफ होगा। कैट के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की ऐसे समय में जब देश में कर प्रणाली के सरलीकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, किसी भी प्रकार के उपकर जीएससटी की मूल भावना और सिद्धान्त के खिलाफ होगी। उन्होंने कहा की जीएसटी कानून के अंतर्गत सरकार को कोई भी उपकर लगाने का अधिकार है, लेकिन यह विशेष परिस्थितियों में ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से केरल को बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता दी जानी चाहिए किन्तु उपकर लगाने की स्थान पर सरकार भारत सरकार की संचित निधि में से गैर योजना मद में यह सहायता दी जा सकती है। जीएसटी परिषद ने पिछले सप्ताह बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया है जो केरल जैसी प्राकृतिक आपदा प्रभावित राज्यों के लिए कुछ माल एवं सेवाओं पर नया कर लगाने की कानूनी वैधता पर विचार करेगी। कैट ने कहा कि यदि ऐसा कोई उपकर लगाया जाता है तो एक तरफ सरकार को अपने सॉफ्टवेयर के ढांचे में बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा दूसरी तरफ व्यापारियों को भी अपनी कर प्रणाली में कर और रिटर्न से संबंधित कई बदलाव लाने होंगे। ! कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री, जीएसटी परिषद और उपकर के लिए गठित मंत्री समूह से आग्रह किया है की केरल की मदद की लिए उपकर लगाने के बजाय कोई अन्य विकल्प इस्तेमाल किया जाए।

IMF, WTO और वर्ल्ड बैंक ने सेवा क्षेत्र को उदार बनाने का आह्वान किया

वाशिंगटन। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक (WT) विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने रविवार को सामूहिक रूप से सेवा क्षेत्र में व्यापार उदारीकरण का आह्वान किया। इन संगठनों ने कहा कि इस क्षेत्र में आज उतनी ही बाधाएं हैं, जितनी करीब 50 साल पहले वस्तु व्यापार में थी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्वबैंक और विश्व व्यापार संगठन की ओर से संयुक्त रूप से जारी 'रिइनविगोरेटिंग ट्रेड एंड इन्क्लुसिव ग्रोथ' (व्यापार और समावेशी वृद्धि को सशक्त बनाना) शीर्षक रिपोर्ट में यह बात कही गयी है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन ऐसे समय में किया गया है जब ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा के मुद्दे पर काफी कड़ा रुख अख्तियार किया है। इस कदम से आईटी पेशेवर और काफी कुशल भारतीय व्यक्तियों के साथ-साथ आईटी क्षेत्र से जुड़ी बड़ी भारतीय कंपनियां भी प्रभावित हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक जीडीपी और रोजगार में सेवा क्षेत्र का योगदान एक तिहाई है। इसके बावजूद सेवा क्षेत्र को अधिक उदार नहीं बनाये जाने से पूरे क्षेत्र और अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और कारोबार पर फर्क पड़ता है।

ईरान पर प्रतिबंध के बाद भारत के लिए तेल आपूर्ति के नए विकल्प तलाश रहा अमेरिका

न्यूयॉर्क। एजेंसी

ईरान पर प्रतिबंध के बाद भारत के लिए तेल आपूर्ति के वैकल्पिक रास्तों को लेकर अमेरिका गंभीर है। ट्रंप प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि ईरान पर चार नवंबर से कड़े प्रतिबंध लागू होने के बाद भारत में तेल के आयात की जरूरत को अमेरिका समझता है। अधिकारी ने कहा, 'हमारे मित्र भारत के लिए वैकल्पिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को बातचीत की जा रही है जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर नहीं पड़े।' ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया रीजन की प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने कहा, 'अमेरिका अपने सभी मित्रों और सहयोगियों से प्रतिबंध के लागू होने पर विमर्श कर रहा है। हम भारत के तेल आयात की जरूरत को समझते हैं। इस चर्चा का हिस्सा भारत को तेल की वैकल्पिक आपूर्ति सुनिश्चित करना है ताकि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर न पड़े।' उन्होंने कहा कि भारत की निजी क्षेत्र की कंपनियां कच्चे तेल के नए आपूर्तिकर्ताओं के विकल्प तलाश रही हैं। साथ ही प्रतिबंध को लेकर भारत व अमेरिका के विशेषज्ञ चर्चा भी कर रहे हैं। चाबहार बंदरगाह परियोजना को लेकर वेल्स ने कहा कि इस पर भी समीक्षा हो रही है। अफगानिस्तान के हित में भारत के कदमों की अमेरिका सराहना करता है और इन कदमों में चाबहार बंदरगाह की भूमिका को भी समझा जा सकता है। इस पर बात से पहले इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में अमेरिका 2015 के ईरान परमाणु समझौते से पीछे हट गया था और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। पहले चरण का प्रतिबंध पहले से ही प्रभावी है और चार नवंबर से प्रतिबंध पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। अमेरिका मान रहा है कि प्रतिबंध के बाद भारत सहित सभी देश ईरान से तेल आयात शून्य पर ले आएंगे। अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि ईरान के साथ जो भी देश व्यापार करेगा, उसे अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय प्रणाली से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। हालांकि इस प्रतिबंध पर संयुक्त राष्ट्र की मुहर नहीं लगी है। पारंपरिक तौर पर भारत हमेशा सिर्फ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को ही मानता रहा है। फिलहाल ईरान से तेल का आयात करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक भारत ने वहां से तेल का आयात कम कर दिया है, लेकिन ऐसे संकेत दिए हैं कि ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे खत्म नहीं किया जाएगा।

गंगा जलमार्ग पर माल ढुलाई 2021 तक 2.18 करोड़ टन तक पहुंच जायेगी

नई दिल्ली। एजेंसी

गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग-एक पर अगले दो से तीन साल में माल ढुलाई बढ़कर 2.18 करोड़ टन से अधिक हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा जल संसाधन एवं गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को प्रोत्साहन देने के उपाय कर रही है, जिससे माल यातायात तेजी से बढ़ेगा। गडकरी ने कहा कि नदी परिवहन को प्रोत्साहन देने के लिए 13 मानकीकृत अत्याधुनिक जहाज डिजाइन तैयार किये गये हैं। इससे गंगा नदी मार्ग में चलने वाले जहाजों के आकार को लेकर किसी अस्पष्ट स्थिति को समाप्त किया जा सकेगा। गडकरी ने कहा, "हमने अंतर्देशीय जल परिवहन को प्रोत्साहन के कई उपाय किए हैं, जिन पर अभी ध्यान नहीं दिया गया। एक अध्ययन के अनुसार 2021 तक राष्ट्रीय जलमार्ग एक पर माल यातायात 2.18 करोड़ टन पर पहुंच जाएगा।" राष्ट्रीय जलमार्ग एक पर 2017-18 में माल परिवहन 55 लाख टन रहा था। मंत्री ने कहा कि फिलहाल राष्ट्रीय जलमार्ग एक पर कई परियोजनाएं चल रही हैं। इसकी टर्मिनल क्षमता 1.36 करोड़ टन की है। इनमें वाराणसी, हल्दिया और साहेबगंज मल्टीमॉडल केन्द्र शामिल हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) 13 जहाजों के डिजाइन लेकर आ रहा है। इससे घरेलू जहाज निर्माण उद्योग के लिए स्थिति सुगम हो सकेगी। सरकार राष्ट्रीय जलमार्ग एक वाराणसी हल्दिया मार्ग पर नौवहन के विस्तार के लिए जल मार्ग विकास परियोजना जेएमवीपी का क्रियान्वयन कर रही है। इस पर 5,369.18 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके लिए विश्व बैंक से तकनीकी सहायता और निवेश सहयोग मिला है। गडकरी ने बताया कि नए डिजाइनों से जहाज बनाने पर 30 से 50 लाख रुपये की बचत होगी।

मोबाइल फोन एक्सपोर्ट पर कंपनियों ने मांगी टैक्स छूट

नई दिल्ली। चीन और वियतनाम की तुलना में भारत को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हैंडसेट कंपनियों ने मोबाइल फोन के एक्सपोर्ट पर 10 वर्ष की टैक्स छूट मांगी है। इन कंपनियों का कहना है कि ऐसा न होने पर देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने और इम्पोर्ट कम करने के सरकार के लक्ष्य का पूरा होना मुश्किल है। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों की योजना फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम (इफ्ज) के जरिए देश में कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और थ्रू स्क्रीन जैसे महत्वपूर्ण प्रॉडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों के लिए देश में प्लांट लगाने का आकर्षण अभी बहुत कम है।

इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) के चेयरमैन पंकज महेन्द्रू ने ईटी को बताया, 'अभी यह इंडस्ट्री देश से न के बराबर एक्सपोर्ट कर रही है। इस इंडस्ट्री के मजबूत होने पर सरकारी खजाने को इनकम टैक्स और एएऊ कलेक्शन से फायदा होगा।' उन्होंने कहा कि ICEA ने इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन और इनफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को ज्ञापन दिए हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट को रोकने के लिए सरकार इम्पोर्ट को कम करने और एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर जोर दे रही है। देश में हैंडसेट सहित इलेक्ट्रॉनिक प्रॉडक्ट्स का बड़ी मात्रा में इम्पोर्ट किया जाता है।

हैंडसेट कंपनियों को एक्सपोर्ट के लिए प्रोत्साहन देने का कोई कदम आईफोन बनाने वाली एपल की मांगों के अनुसार होगा। एपल भारत से एक्सपोर्ट के लिए सरकार से टैक्स में छूट की मांग कर रही है। दक्षिण कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग ने हाल ही में भारत

में अपना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है। सैमसंग की योजना भारत में अपने प्रॉडक्शन के एक बड़े हिस्से का एक्सपोर्ट करने की है। इफ्ज का पहला चरण सफल रहा है और इसमें 120 नए प्लांट लगाए गए हैं। इंडस्ट्री के पास अगले पांच से सात वर्षों में 500 अरब डॉलर के टर्नओवर तक पहुंचने की क्षमता है। इसमें से 230 अरब डॉलर मोबाइल फोन और 270 अरब डॉलर कंपोनेंट से आ सकता है। हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले पांच से सात वर्षों में 1.25 अरब मोबाइल फोन बनाने और इसमें से 80 करोड़ का एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य अभी बहुत महत्वाकांक्षी दिख रहा है। इसके लिए सरकार को चीन और वियतनाम की तर्ज पर टैक्स में छूट देनी होगी। सरकार ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में देश में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कैमरा मॉड्यूल और कनेक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की योजना बनाई है। 2019-20 में डिस्प्ले असेंबली, टच पैनल और वाइब्रेटर मोटर जैसे कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जाएगा।

भारत ने WTO से कहा

वैश्विक नियमों के मुताबिक है कृषि निर्यात नीति

नई दिल्ली। भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (WTO) को बताया है कि उसकी प्रस्तावित कृषि निर्यात नीति वैश्विक व्यापार नियमों के अनुसार होगी। विभिन्न देशों की कृषि नीतियों की समीक्षा के लिए पिछले सप्ताह हुई एक मीटिंग में भारत की प्रस्तावित नीति पर विचार-विमर्श किया गया था। भारत की कृषि निर्यात नीति के वैश्विक असर को लेकर आशंकाएं जताई गई हैं। इस नीति का उद्देश्य न्यूनतम निर्यात मूल्य जैसी बंदिशों या प्रतिबंधों का समाप्त करना है जिससे देश से कृषि उत्पादों का निर्यात 2022 तक बढ़ाकर 60 अरब डॉलर से अधिक करने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

यूरोपियन यूनियन ने उन उपायों के विवरण मांगे हैं जिनका इस्तेमाल इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन ने यह पूछा है कि ये उपाय किस तरह देश के किसानों को मिलने वाली ऐसी सहायता को नहीं बढ़ाएंगे, जिससे ट्रेड को नुकसान होता है। इसके अलावा भारत से यह भी पूछा गया है कि क्या दोगुना करने का लक्ष्य औसत कृषि आमदनी से जुड़ा है और क्या भारत इसके लिए 'ग्रीन बॉक्स' सब्सिडी का

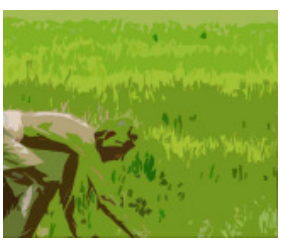

इस्तेमाल करना चाहता है।

ग्रीन बॉक्स सब्सिडी ट्रेड को नुकसान न पहुंचाने वाली सब्सिडी होती है और WTO इस सब्सिडी की अनुमति देता है। भारत ने मई में WTO को बताया था कि देश की ग्रीन बॉक्स सब्सिडी 2015-16 में घटकर 18.3 अरब डॉलर पर आ गई थी, जो 2014-15 में 20.8 अरब डॉलर थी। 2015-16 में ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में फूड सिक्योरिटी के उद्देश्यों से पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग पर 15.6 अरब डॉलर खर्च किए गए थे। इससे पिछले वर्ष यह राशि 17.1 अरब डॉलर की थी। भारत ने WTO को जानकारी दी है कि विभिन्न नीतियों के साथ उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता किसानों को मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और संबंधित खर्चों के लिए मुआवजा देने के उद्देश्य से थी। इसके लिए WTO की ओर से अनुमति है। WTO को भारत ने बताया है कि प्रस्तावित कृषि निर्यात नीति पर अभी विचार किया जा रहा है लेकिन यह WTO के नियमों के अनुसार होगी। इस नीति को प्रधानमंत्री कार्यालय अनुमति मिल गई है। इसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जा सकता है। एक अधिकारी ने कहाकि नीति को लेकर अन्य देशों की वास्तविक आशंकाओं का ध्यान रखा जाएगा।

जेब पर भारः बैंकों ने बढ़ाई ब्याज दरें

महंगा हुआ होम-कार लोन

बैंक लोन	पुराना दर	नया दर	30 लाख के होम पर दर
एसबीआइ	8.45%	8.50%	8.70-8.85%
एचडीएफसी	8.75%	8.85%	8.70-8.85%
आईसीआईसीआई	8.50%	8.60%	8.85%

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा से पहले ही भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और पीएनबी ने अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी। इसके चलते पहले से लिए होम-कार लोन की ईएमआई बढ़ गई है तो नया लोन लेना महंगा हो गया है।

किसने बढ़ाई कितनी ब्याज दरें: एसबीआई ने 0.05 प्रतिशत, आईसीआईसीआई बैंक ने 0.1 प्रतिशत, पीएनबी ने 0.2 प्रतिशत एमसीएलआर में बढ़ोतरी की है। वहीं एचडीएफसी ने भी रिटेल प्राइस लेंडिंग रेट (आरपीएलआर) में 0.10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) वह दर है, जिसपर बैंक 2016 से कर्ज पर ब्याज दर तय करती है। इसमें इजाफा का मतलब है कि कर्ज महंगा हो गया।

RBI दे सकता है तीसरा झटका

अक्तूबर में फिर बढ़ा सकता है ब्याज दर ब्याज दरों में और बढ़ोतरी संभव अगर आरबीआई मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों में वृद्धि होती है तो आने वाले दिनों में लोन लेना और महंगा हो सकता है। ऐसा बैंकों को आरबीआई से कर्ज लेना महंगा होने के कारण होगा। ऐसी उम्मीद है कि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में वृद्धि के बाद आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है।

गौरतलब है कि इससे पहले अगस्त की बैठक में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। इसके साथ रेपो रेट 6.50 प्रतिशत हो गया था। रुपये में गिरावट और कच्चे तेल के दाम में तेजी को देखते हुए रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। आरबीआई का मानना है कि रुपये में डॉलर के मुकाबले गिरावट से और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई पर दबाव बढ़ेगा। इससे महंगाई में इजाफा हो सकता है। महंगाई को रोकने के लिए आरबीआई ब्याज दरों में इजाफा कर सकता है।

बीमा ब्रोकिंग में 100 प्रतिशत एफडीआई पर विचार रही है सरकार

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार बीमा ब्रोकिंग क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार के इस कदम से इस क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकेगा। फिलहाल एफडीआई नीति के तहत बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है। औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) की परिभाषा के अनुसार इसमें बीमा ब्रोकिंग, बीमा कंपनियां, तीसरा पक्ष प्रशासक, निरीक्षणकर्ता और नुकसान का आकलन करने वाले शामिल हैं। डीआईपीपी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की इकाई है, जो एफडीआई से संबंधित मामलों को देखती है और देश में कारोबार सुगमता की स्थिति के लिए काम करती है। समय-समय पर सरकार से यह मांग की जाती रही है कि बीमा ब्रोकरों को अन्य वित्तीय सेवा मध्यस्थ इकाइयों के समान माना जाना चाहिए। इन इकाइयों में शतप्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। सूत्रों ने कहा कि बीमा ब्रोकिंग किसी अन्य वित्तीय या जिंस ब्रोकिंग सेवा की तरह है। इस मुद्दे पर हाल में एक उच्चस्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक में विचार हुआ। सरकार सकारात्मक तरीके से इस पर विचार कर रही है। अधिकारी ने हालांकि स्पष्ट किया कि बीमा कंपनियों के लिए एफडीआई की सीमा 49 प्रतिशत ही है। वित्त मंत्री ने हाल में इस विषय पर बैठक की थी। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने भी इस बारे में डीआईपीपी से विचार मांगे हैं। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि बीमा क्षेत्र कमजोर वितरण नेटवर्क से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में वितरण नेटवर्क को मजबूत करने की जरूरत है।

करेंसी नोट पर गांधी की तस्वीर पहली बार उनकी जन्मशती पर प्रकाशित हुई

नयी दिल्ली। एजेंसी

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर देश के करेंसी नोट पर पहली बार उनके जन्मशती वर्ष में प्रकाशित की गई थी। यह मौका करीब 50 साल पहले आया जब 100 रुपये के नोट में राष्ट्रपिता की तस्वीर प्रकाशित की गई। हालांकि, वर्ष 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही यह महसूस किया गया कि करेंसी नोटों में ब्रिटिश सम्राट के चित्र की जगह महात्मा गांधी की तस्वीर होनी चाहिए, लेकिन सरकार को इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने में काफी समय लग गया। इस बीच, करेंसी नोट में ब्रिटेन सम्राट का स्थान सारनाथ के अशोक चिन्ह ने ले लिया। रिजर्व बैंक ने पहली बार वर्ष 1969 में 100 रुपये का एक स्मारक नोट जारी किया जिसमें सेवाग्राम आश्रम में बैठे महात्मा गांधी को दिखाया गया था। लेकिन करेंसी नोट में राष्ट्रपिता की तस्वीर को नियमित रूप से प्रकाशित करने का

काम 1987 में ही शुरू हो पाया। इस साल 500 रुपये के नोट की नई श्रंखला में मुस्कराते हुये महात्मा गांधी का चित्र छापा गया। तब से महात्मा गांधी का चित्र नियमित रूप से विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों में छापा जाने लगा। गांधी का चित्र छापने से पहले मुद्रा नोटों में कई डिज़ाइन और छवियों का उपयोग किया गया। वर्ष 1949 में तत्कालीन सरकार ने अशोक स्तंभ के साथ एक रुपये का नया नोट जारी किया। वर्ष 1953 में जारी नए नोटों में हिंदी को प्रमुखता के साथ स्थान दिया गया। हिंदी में रुपया के बहुवचन को लेकर जो बहस उस समय चल रही थी वह अंत में रुपये शब्द पर जाकर समाप्त हुई। उच्च मूल्य वर्ग के नोटों (1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये) को 1954 में पुनः जारी किया गया। इसके बाद 1980 में नोटों की बिल्कुल नयी श्रृंखला शुरू की गई। इनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लेकर तेल उत्खनन और कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण के चित्रों पर जोर दिया गया।

किसानों की नाराजगी दूर करने बढ़ सकते है रबी के फसलों के दाम

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

2019 के चुनाव से पहले किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए हर तरह की कोशिश करने में सरकार लगी हुई है। राजनीतिक दल जानते है कि इस देश में किसानों को नाराज करके कोई भी पार्टी सरकार में नहीं आ सकती। पिछले कुछ वक्त से जिस तरह किसान केन्द्र सरकार के खिलाफ गोलबंद हुए हैं, इससे सरकार भी चिंतित है। किसानों की इसी नारजगी को दूर करने के लिए मोदी सरकार रबी की फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने का एलान कर सकती है।

6 फसलों का बढ़ाए जा सकते हैं दाम

सरकार गेहूं समेत 6 रबी की फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने का एलान कर सकती है। कैबिनेट की बैठक में गेंहू का मूल्य 105 रुपए प्रति क्विंटल, चना का समर्थन मूल्य 220 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर का मूल्य 225 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों का मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल और जौ का समर्थन मूल्य भी 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए जा सकते हैं।

कुछ इस तरह से होंगी नई दरें

रबी की इन फसलों के दाम बढ़ाए जाने के लिए जो प्रस्ताव दिया जा रहा है, इसके लागू होने के बाद गेहूं 1840 रुपए प्रति क्विंटल, चना 4620 रुपया प्रति क्विंटल, मसूर 4475 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों का मूल्य 4200 रुपए प्रति क्विंटल, जौ का समर्थन मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1440 रुपए प्रति क्विंटल हो सकता है।

देश का भंडारण क्षेत्र 2021 तक 29.70 करोड़ वर्गफुट तक पहुच जाने का अनुमानः रिपोर्ट

मुंबई। देश के आठ प्रमुख शहरों में भंडारगृह क्षमता सालाना 21% की दर से बढ़कर 2021 तक 29.7 करोड़ वर्गफुट हो जाने की उम्मीद है। एक रपट में कहा गया है कि इसकी अहम वजह भंडारण क्षेत्र को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाना और माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के लागू होने की वजह से मांग बढ़ना है। परामर्श कंपनी केपीएमजी ने अपनी रपट में कहा कि देश में आठ शहरों मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, अहमदाबाद, बेंगलुरू, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में वर्ष 2019 तक भंडारण स्थान बढ़कर 20.4 करोड़ वर्गफुट तक पहुंच जाने की संभावना है। रपट में कहा गया है कि देश का भंडारण उद्योग 2017 में करीब 56,000 करोड़ रुपये का रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद उद्योग को काफी बढ़ावा मिला है। भंडारण उद्योग में लागत बचत और क्षमता में सुधार के साथ उद्योग की मांग बढ़ी है। पिछले साल नवंबर में सरकार ने लॉजिस्टिक क्षेत्र को बुनियादी ढांचा उद्योग का दर्जा दे दिया था। इसमें भंडारण सुविधाएं, शीतगृह और औद्योगिक पार्क शामिल हैं। इसके साथ ही छोटे छोटे फैले हुये भंडारगृह अब मिलकर केन्द्रीकृत भंडारगृह के बड़े केन्द्रों के रूप में उभर रहे हैं। इसमें आपूर्ति श्रंखला को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। जीएसटी से पहले 2014-16 में इस क्षेत्र की सालाना वृद्धि 15% थी जबकि जीएसटी के बाद 2017-21 के बीच 21% होने की उम्मीद है।

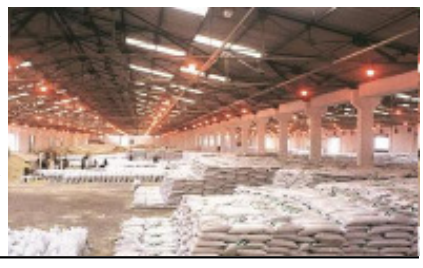

गुरु बिना न ज्ञान संभव, न ईश्वर की प्राप्ति

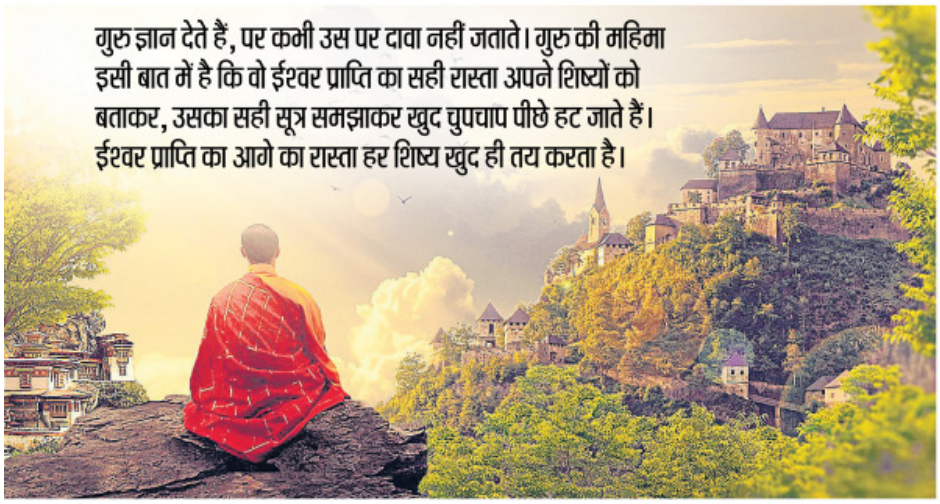

अध्यात्म

आनंदमूर्ति गुरुमां

गुरु का कार्य है शिष्य को तैयार करना। उसके जीवन में वैराग्य की, प्रेम की जगह बनाना, उसको जिज्ञासु बनाना। लेकिन एक बार साधना के जगत में उतर जाने के बाद का काम फिर शिष्य का ही होता है। हां, साधना करते समय शिष्य में कोई संशय, कोई दिक्कत, कोई प्रश्न उठ जाए, तो फिर वह गुरु के पास जाए। गुरु फिर करुणा करके संभालेंगे, तुम्हारी शंकाओं का समाधान करेंगे, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। परंतु साधना के पथ पर सत्य यही है कि मेरे और परमात्मा के बीच गुरु भी नहीं आ सकते।

सच बात यह है कि गुरु आना भी नहीं चाहते। वे बीच में क्यों आएंगे? तुमको ईश्वर की प्राप्ति करनी है या गुरु की? हां, यह भी सत्य है कि गुरु के बगैर इस मार्ग पर चलना हो नहीं सकता, इसलिए गुरु की महिमा कम नहीं हो सकती। लेकिन जो बात मैं कह रही हूं, उसे समझने की कोशिश करिए। गुरु की महिमा इसी में है कि वे तुम्हें तैयार करते हैं, करुणावश तुम्हें सब कुछ देते हैं, तुम्हें ज्ञान, ध्यान के सूत्र देते हैं। एक बार तुमने उन सूत्रों को अंगीकार कर लिया, तो वे चुपके से पीछे हट जाते हैं। वो एहसान भी नहीं जताते, बल्कि तुम्हें साधना में पुलकित होते देखकर प्रसन्न होते हैं।

आप गुरु को या संत को प्रणाम करना चाहते हो। सच बात यह है कि प्रणाम करने का तरीका अगर आता हो, तो प्रणाम करना ही अपने आपमें बहुत बड़ी ध्यान की विधि है। पूरे भाव और प्रेम के साथ हाथ जुड़े हों, तो सिर्फ सिर ही नहीं झुकता, सिर के साथ खुद भी झुक जाते हो। अगर इस तरह कोई भावपूर्ण प्रणाम करना जानता हो, तो सच बात यह है कि फिर कोई मंदिर, गुरुद्वारे की भी जरूरत नहीं रह जाती। परमात्मा सर्वत्र है, उसका स्मरण करते हुए, कहीं पर भी प्रणाम किया जा सकता है। ज्ञान की दृष्टि कहती है कि जिसने पहले परमात्मा को अपने अंतर में जान लिया हो, उसको चारों दिशाओं में परमात्मा का अस्तित्व महसूस होने लगता है।

'बाहर ढूंढन ते हम चूक परे, गुरु घर ही माहे दिखाया।' भक्त कहता है, अब मुझको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे भीतर परमात्मा का होना कैसा है, यह मुझको मेरे गुरु ने समझाया है। गुरु वह मित्र होता है, जो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा को सुगम करने के लिए ही तुम्हारे पास है। असली गुरु तुम्हारे ही भीतर है। लेकिन तुम्हारे और उसके बीच एक दीवार खड़ी है। उसकी वजह से तुम्हारा और उसका संपर्क टूटा हुआ है। इसलिए बाहर के गुरु की जरूरत पड़ती है, ताकि वे तुम्हें अपने भीतर के ज्ञानरूप गुरु से जुड़ना सिखा दें।

आप मामूली नहीं हो, आप खास हो। आप इसलिए खास हो, क्योंकि परमात्मा खुद आपके हृदय में वास करता है। आप सब चलते-फिरते मंदिर हो। और किस मंदिर में जाओगे? सच बात बोलूं तो कभी यह भी कर के देख लेना कि मंदिर में जाने का भाव चित्त में हो, तो दो फूल लेकर अपने ही सिर पर चढ़ा लेना और अंदर बैठे भगवान से कहना कि 'मेरे इन फूलों को स्वीकार करो।'

बाहर की मूर्ति पर फूल चढ़ाने का आनंद तुम्हें आए या न आए, लेकिन जिस भावदशा में मैं यह बात कह रही हूं, अगर इसी भावदशा में तुम अपनी ही देह की पूजा कर पाए, तो एक अद्भुत अनुभूति होगी। जब अपनी ही देह मंदिर हो चुकी हो, तो क्या जरूरत है किसी मंदिर में जाने की? लेकिन नासमझी और अज्ञान के कारण मनुष्य अपने आपको देख ही नहीं पाता।

बाहर के मंदिर भी बेकार नहीं हैं। इन मंदिरों का बहुत उपयोग है, क्योंकि शायद इन मंदिरों में जाते-जाते कभी किसी दिन इस बात की समझ तुमको लग जाएगी कि असली मंदिर खुद तुम्हारा अपना यह शरीर ही है। बाहर मंदिर में रखी मूर्ति किसी मूर्तिकार ने पत्थर से गढ़ी होगी। वह टूट सकती है, तोड़ी जा सकती है। लेकिन यह तुम्हारी शरीर रूपी मूर्ति खुद परमात्मा ने अपने हाथों से बनाई है। दुनिया की कोई भी मूर्ति तुम्हारे शरीर का मुकाबला नहीं कर सकती। इस कायनात के रचनाकार ने खुद पंचतत्वों की मिट्टी लेकर तुम्हारे जिस्म को रचा। फिर इसी जिस्म में फूंक मारकर प्राण भी भर दिए और खुद ही आकर तुम्हारे अंदर विराजमान हो गया।

'उतरा सागर में उसको ही मोती मिला' इसलिए सागर के किनारे मत बैठे रहिये, सागर के भीतर उतरिए। जितनी गहराई में उतरते जाओगे, उतने ही ज्ञान के मोती तुम्हें प्राप्त होंगे, तुम उतने ही धनवान होते जाओगे।

आस्था स्थली : चन्नकेशव पेरुमाल, चेन्नई

इस मंदिर पर पड़ा चेन्नई का नाम

चन्नकेशव पेरुमाल मंदिर चेन्नई के प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल है। इसे पत्तनाम कोविल के नाम से भी जाना जाता है। चेन्नई शहर का नाम इसी मंदिर के नाम पर पड़ा। पहले चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। पर 17 जुलाई, 1996 को इस शहर का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर चेन्नई किया गया।

चेन्ना वास्तव में कन्नड़ भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है बढ़िया और सुंदर। ब्रिटिश राज से पहले यह शहर चेन्नापटनम के नाम से जाना जाता था। तमिल में चेन्नी का मतलब होता है चेहरा। तो ये मंदिर चेन्नई शहर का चेहरा है। चेन्नई के जॉर्ज टाउन इलाके का यह मंदिर पुराने समय में मद्रास के न्यू सेटलमेंट एरिया में ब्रिटिश कालोनी बसने के दौरान बना था।

चेन्नकेशव पेरुमाल मतलब भगवान विष्णु। इन्हें चेन्नई शहर का संरक्षक और पालक देवता माना जाता है। चेन्नई के इतिहासकार बताते हैं चेन्नकेशव और चेन्नमालेश्वर मंदिर पहले वर्तमान हाईकोर्ट भवन के पास हुआ करते थे। ब्रिटिश शासन में शहर के नवनिर्माण के दौरान इन मंदिरों को यहां स्थानांतरित किया गया। फोर्ट सेंट जॉर्ज के आसपास शहर में नए भवनों के निर्माण के लिए पुराने मंदिरों को ब्रिटिश सरकार ने हटा दिया था। मद्रास हाईकोर्ट के पास स्थित पुराने चन्नकेशव मंदिर को 1757 में नष्ट कर दिया गया था। इसी के बाद मनाली मुत्थु कृष्ण मुदालियार ने सन 1762 में वर्तमान स्थल साहुकार पेट में दोनों मंदिरों का निर्माण करवाया। ब्रिटिश सरकार ने मंदिर के लिए जमीन का एक हिस्सा उपलब्ध कराया, पर मंदिर का निर्माण लोगों के सहयोग से हुआ। चन्नकेशव मंदिर के बगल में शिव के मंदिर का भी निर्माण कराया गया।

चन्नकेशव मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। निर्माण में पत्थरों का प्रयोग ज्यादा हुआ है। मंदिर के गर्भ गृह में भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा है। प्रतिमा सुनहरे रंग की है। गर्भ गृह के चारों तरफ विशाल गलियारा है। मंदिर परिसर में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ आस्थावान श्रद्धालु पूजा में लीन दिखाई देते हैं। पोंगल मंदिर का प्रमुख त्योहार है।

मंदिर खुलने का समय : मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और दोपहर 12 बजे बंद हो जाता है। फिर शाम को 4.30 बजे खुलता है और रात को 9 बजे बंद हो जाता है। चन्नकेशव का मंदिर पुराने मद्रास के भीड़भाड़ वाले इलाके में है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दो द्वारपाल की मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर में भगवान की विशाल प्रतिमाओं के फोटो फ्रेम वाली दुकानें भी हैं।

कैसे पहुंचें : चन्नकेशव पेरुमाल मंदिर चेन्नई में साहुकार पेट नामक जगह पर है। चेन्नई रेलवे स्टेशन से यहां पहुंचने का आसान रास्ता है कि आप वालटेक्स रोड पर आधा किलोमीटर चलकर जाएं, फिर साहुकार पेट वाले मोड़ से एनसीबीएस रोड पर अंदर जाएं। आगे तिराहे पर देवराज मुदाली स्ट्रीट के कोने में चन्नकेशव मंदिर स्थित है।

-विद्युत प्रकाश मौर्य

बोध कथा

मां सीता और तिनके का रहस्य

रावण जब मां सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया, तब लंका में मां सीता वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगीं। रावण बार-बार आकर उन्हें धमकाता, लेकिन सीताजी कुछ न बोलतीं। यहां तक कि रावण ने श्रीराम की वेशभूषा में आकर सीता को भ्रमित करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हुआ। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला।

रावण एक बार फिर सीता के पास आया और बोला, 'मैं तुमसे सीधे-सीधे संवाद करता हूं, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर-घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है?' रावण के इस प्रश्न को सुनकर सीताजी बिल्कुल चुप हो गईं और उनकी आंख से आसुओं की धार बहने लगी। हुआ यों कि जब श्री राम का विवाह मां सीता के साथ हुआ, तब सीताजी का बड़े आदर-सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। जैसी कि प्रथा है कि नववधू, जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवनभर घर पर मिठास बनी रहे। इसलिए सीताजी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई। समस्त परिवार, राजा दशरथ सहित चारों भ्राता और ऋषि-मुनि भी भोजन पर आमंत्रित थे। मां सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया। भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी-अपनी पत्तल संभाली। सीताजी देख रही थीं, ठीक उसी समय राजा दशरथ की खीर पर एक छोटा-सा घास का तिनका गिर गया। सीताजी ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, यह प्रश्न आ गया।

मां सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूरकर देखा। वह तिनका जलकर राख में तब्दील हो गया। सीता ने सोचा अच्छा हुआ, किसी ने नहीं देखा। पर, राजा दशरथ सीता का यह चमत्कार देख रहे थे। दशरथ उस समय चुप रहे और अपने कक्ष में चले गए और सीता को बुलवाया। राजा दशरथ ने सीता से कहा, 'मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा था, उस नजर से आप अपने शत्रु को भी मत देखना।'

यही वजह थी कि सीताजी के सामने जब भी रावण आता था तो वह उस घास के तिनके को उठाकर दशरथ जी की बात याद कर लेती थीं। यही है उस तिनके का रहस्य। सीताजी चाहतीं तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थीं, लेकिन राजा दशरथ को दिए गए वचन की वजह से वे शांत रहीं।

कृषि जनगणना के आंकड़े जारी

कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने सोमवार को वर्ष 2015-16 की कृषि जनगणना रिपोर्ट जारी की जिसमें खेती के रकबे में वर्ष 2010-11 की तुलना में 1.53 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इस गणना के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, देश में खेती का रकबा 15 करोड़ 71.4 लाख हेक्टेयर है। इस दौरान कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, 2015-16 में कृषि जोत का औसत आकार घटकर 1.08 हेक्टेयर रह गया। 2010-11 में यह 1.15 हेक्टेयर था।

गणना रिपोर्ट के अनुसार, 2010-11 में कृषि जोत रखने वालों में महिलाओं का हिस्सा 12.79 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 13.87 प्रतिशत हो गया। इसी तरह खेती के रकबे के हिसाब से महिलाओं का हिस्सा 10.36 प्रतिशत से बढ़कर 11.57 प्रतिशत हो गया। एक सरकारी बयान में कहा गया है, 'इससे पता चलता है कि कृषि भूमि के प्रबंध और परिचालन में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है।'

कृषि मंत्रालय ने कहा है कृषि-जनगणना केलिए आधार वर्ष 1970-71 रखा गया है। यह गणना, खेती की भू-धारिता के संरचनात्मक पहलुओं के आंकड़े जुटाने के लिए हर पांच साल पर की जाती है। यह इसकी 10वीं कड़ी है। बयान में कहा गया है, 'वर्ष 2010-11 में देश में खेती जोत की कुल संख्या 13.8 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 14.6 करोड़ हो गई है। यह इसमें 5.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।' इसके विपरीत खेती-बाड़ी का कुल रकबा 2010-11 के 15 करोड़ 95.9 लाख हेक्टेयर से घटकर 2015-16 में 15 करोड़ 71.4 लाख हेक्टेयर रह गया। ताजा कृषि गणना

कुल जोत में लघु एवं सीमांत जोत (दो हेक्टेयर से कम की जोत) का अनुपात 86.21 प्रतिशत है। 2010-11 में ऐसी जोता का हिस्सा 84.97 प्रतिशत था। कुल कृषि क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों के पास की जमीन का हिस्सा इस समय 47.34 प्रतिशत है। 2010 - 11 में यह हिस्सा 44.31 प्रतिशत था। वर्ष 2015-16 में अर्ध-मध्य और मध्य आकार वाली जोतों (दो से 10 हेक्टेयर) का हिस्सा संख्या के हिसाब से 13.22 प्रतिशत और क्षेत्र फल के हिसाब से 43.61 प्रतिशत हिस्सा था। वर्ष 2015-16 में बड़ी जोत (10 हेक्टेयर या ऊपर) वाले किसान 0.57 प्रतिशत थे और उनके पास का रकबा कुल कृषि रकबे का 9.04 प्रतिशत था। 2010-11 में उनकी संख्या 0.71 प्रतिशत और उनका रकबा कुल रकबे का 10.59 प्रतिशत था। देश भर में कुल 14.6 करोड़ जोत में उत्तर प्रदेश दो करोड़ 38.2 लाख भू.धारकों की संख्या के साथ पहले स्थान पर था। इसके बाद बिहार (एक करोड़ 64.1 लाख), महाराष्ट्र (एक करोड़ 47.1 लाख), मध्य प्रदेश (एक करोड़), कर्नाटक में (86.8 लाख), आंध्र प्रदेश (85.2 लाख), तमिलनाडु (79.4 लाख), राजस्थान (76.5 लाख) और पश्चिम बंगाल (72.4 लाख) का नंबर आता है। कुल कृषि क्षेत्र में राजस्थान का हिस्सा दो करोड़ 8.7 लाख हेक्टेयर, महाराष्ट्र का एक करोड़ 98 लाख हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश एक करोड़ 74.5 लाख हेक्टेयर, मध्य प्रदेश एक करोड़ 56.7 लाख हेक्टेयर और कर्नाटक का हिस्सा एक करोड़ 17.2 लाख हेक्टेयर था। जोतों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 12.74 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद आंध्र प्रदेश 11.85 प्रतिशत, राजस्थान 11.12 प्रतिशत, केरल 11.02 प्रतिशत, मेघालय 10.9 प्रतिशत, कर्नाटक 10.78 प्रतिशत और नागालैंड में 10.5 प्रतिशत दर्ज की गई है। हालांकि, गोवा में जोत की संख्या में सबसे अधिक (28.17 प्रतिशत) गिरावट दर्ज की गयी। मणिपुर में गिरावट न्यूनतम (0.0 9 प्रतिशत) रही।

गणना के अनुसार कुल जोतों की संख्या का 91.03 प्रतिशत और कुल क्षेत्र का 88.08 प्रतिशत 14 राज्य- आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के खाते में आता है। व्यक्तिगत, संयुक्त और संस्थागत जोतों की संख्या में पिछली गणना के बाद से क्रमशः 5.04 प्रतिशत, 7.07 प्रतिशत और 10.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तेल मिलों, व्यापारियों की रिफाइंड पामोलिन तेल पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली।एजेंसी

तेल मिलों एवं व्यापारियों ने घरेलू खाद्य तेल उद्योग को बचाने के लिए पामोलिन तेल पर आयात शुल्क को बढ़ाने की मांग की है। उद्योग का कहना है कि घरेलू तेल मिलों

के हित में कच्चे पाम तेल और रिफाइंड पाम तेल के आयात शुल्क के बीच 10 प्रतिशत के अंतर को बढ़ाकर 15 से 20 प्रतिशत किये जाने की आवश्यकता है।

पंजाब ऑयल मिलर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार जैन ने कहा कि सरकार ने कच्चे पाम तेल के आयात पर 44 प्रतिशत और रिफाइंड पाम तेल के आयात पर 54 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया है। इस पर दस प्रतिशत का अधिभार भी लगाया गया है। आयात शुल्क में यह अंतर 10 प्रतिशत है। लेकिन मलेशिया सरकार द्वारा पाम तेल निर्यातकों को इसी अनुपात में सब्सिडी उपलब्ध करा दिये जाने की वजह से शुल्क अंतर का प्रभाव समाप्त हो गया और आयात फिर बढ़ने लगा है। इससे घरेलू तेल रिफाइनरी मिलों को नुकसान हुआ है। तेल मिलों के संगठन के मुताबिक सरकार को कच्चे तेल और रिफाइंड पामोलिन के बीच आयात शुल्क अंतर को 15 से 20 प्रतिशत कर देना चाहिये ताकि देश में रिफाइंड तेल का आयात कम हो। इससे घरेलू रिफाइंड मिलों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल हो सकेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जैन ने कहा कि 1990 में देश खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर था। लेकिन नीतियों पर ध्यान नहीं दिये जाने के कारण पिछले तीन दशक में देश में खाद्य तेल का आयात बढ़ता चला गया। उन्होंने कहा कि खाद्य तेलों पर देश 80 हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करता है। यदि घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए शुल्क बढ़ाया गया तो इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी बचेगा। देश में खाद्य तेलों का आयात हर साल 10 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। पाम तेल में उत्पादकता अधिक होने की वजह से इसकी लागत कम पड़ती है। एक हेक्टयेर पाम खेती से चार टन तक तेल निकलता है जबकि एक हेक्टयेर सरसों की खेती से 350 किलो सरसों तेल प्राप्त होता है।

सूक्ष्म वित्त उद्योग को तीन साल में होगी 6-9 हजार करोड़ रुपये की जरूरतः इक्रा

मुंबई। देश के सूक्ष्म वित्त पोषण क्षेत्र को अपनी वृद्धि योजनाओं के तहत अगले तीन साल में 6-9 हजार करोड़ रुपये की जरूरत पड़ सकती है। एक रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है। इस क्षेत्र ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 25 प्रतिशत की दर से वृद्धि की है। इक्रा ने कहा कि इस क्षेत्र की वृद्धि का परिदृश्य अच्छा बना हुआ है और चालू वित्त वर्ष में इसके 20-22 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया, "इस क्षेत्र को अपनी वृद्धि योजनाओं को पाने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 तक छह से नौ हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी।" इसके मुताबिक निवेशकों का इस उद्योग को लगातार समर्थन मिल रहा है। वित्त वर्ष 2017-18 में इस उद्योग में 4,061 करोड़ रुपये का इक्विटी योगदान दिया गया। इससे पहले 2016-17 में 6,570 करोड़ रुपये का योगदान किया गया। इसमें से 87 प्रतिशत पूंजी क्षेत्र के शीर्ष 10 रिणदाताओं को उपलब्ध कराई गई। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सूक्ष्मवित्त क्षेत्र वार्षिक आधार पर 25 प्रतिशत बढ़कर 2.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। क्षेत्र में बेहतर संग्रह क्षमता, क्षेत्र को निवेशकों का लगातार समर्थन मिलने, कोष की उपलब्धता तथा सूक्ष्म रिण के लिये मांग बने रहने का इसमें योगदान रहा। पहली तिमाही के दौरान सूक्ष्म वित्त उद्योग को संपत्ति गुणवत्ता में सुधार देखने को भी मिला।

वैश्विक संकेतों से सोना 32,000 रुपये के पार, चांदी भी मजबूत

नयी दिल्ली। वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेतों के बीच स्थानीय आभूषण विक्रेताओं की ताजा लिवाली के कारण बुधवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 555 रुपये की तेजी के साथ 32,030 रुपये प्रति दस ग्राम हो गई। औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं का उठाव बढ़ने के कारण चांदी की कीमत भी 39,000 रुपये के स्तर को लांघ गई। बाजार सूत्रों ने कहा कि उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते को बचाने के लिए अमेरिका और कनाडा के एक समझौते पर पहुंचने के बाद सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण कारोबारी धारणा बेहतर हो गई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपये के 73.41 रुपये प्रति डॉलर के सर्वकालिक निम्न स्तर को छूने के बाद आयात महंगा हो गया। इसके कारण भी सोने की कीमतों में तेजी को बल मिला। वैश्विक स्तर पर सिंगापुर में सोना 0.32 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,207.60 डॉलर प्रति औंस हो गया। राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली में सोना 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता की कीमतें 555-555 रुपये की तेजी के साथ क्रमशः 32,030 रुपये और 31,880 रुपये प्रति दस ग्राम बंद हुईं। सोमवार को सोने में 150 रुपये की गिरावट आई थी। गांधी जयंती के मौके पर दो अक्टूबर को सर्राफा बाजार बंद रहा। गिन्नी के भाव भी 100 रुपये की तेजी के साथ 24,600 रुपये प्रति आठ ग्राम पर बंद हुए। तेजी के आम रुख के अनुरूप चांदी हाजिर की कीमत 450 रुपये की तेजी के साथ 39,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। जबकि चांदी साप्ताहिक डिलिवरी की कीमत 460 रुपये की तेजी के साथ 38,980 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। हालांकि चांदी सिक्का लिवाल 73,000 रुपये और बिकवाल 74,000 रुपये प्रति सैकड़ा पर अपरिवर्तित बना रहा।

3R से कमाई कर रहा चिड़ियाघर

प्लास्टिक बना कमाई का साधन

देहरादून। एजेंसी

देश-दुनिया में पर्यावरण के लिए खतरे का सबब बने प्लास्टिक कचरे से पार पाने को उत्तराखंड के देहरादून जू में अपनाई गई थ्री आर यानी रिड्यूस, रीसाइकिल व रीयूज की नायाब पहल रंग ला रही है। इसके बूते यह चिड़ियाघर न सिर्फ प्लास्टिक कचरे से मुक्त हुआ है, बल्कि आय के दरवाजे भी खुले हैं। पानी की बोतल जू के अंदर ले जाने पर आपको 10 रुपये जमा करने होंगे। यदि लौटते समय बोतल साथ न लाए तो जुर्माना।

देहरादून में मसूरी मार्ग पर मालसी में 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है देहरादून जू। जू के निदेशक एवं मुख्य वन संरक्षक पीके पात्रो ने जब पर्यावरण संरक्षण के लिए कमर कसी तो यह नायाब पहल सामने आई। वह बताते हैं कि प्लास्टिक कचरे की मार से यह चिड़ियाघर भी त्रस्त था। सैलानियों द्वारा पानी की खाली बोतलें, पॉलीथिन समेत अन्य सामग्री यहां-वहां फेंक दी जाती थी। वह भी तब जबकि जू में प्लास्टिक, पॉलीथिन पर बैन है।

इस समस्या के निदान के लिए सामने आया थ्री-आर का विचार। हालांकि, रिड्यूस यानी कूड़े में कमी लाने की व्यवस्थाएं बनाई गईं थी, लेकिन यह प्रभावी नहीं हो पा रही थीं। लिहाजा, इसमें रीसाइकिल व रीयूज को शामिल किया गया और इसके बेहतर नतीजे सामने आए हैं।

सालभर के भीतर ही खाली प्लास्टिक की बोतलों से तैयार 60 हजार रुपये मूल्य का चूरा बेचा जा चुका है। यही नहीं, प्लास्टिक की खाली बोतलों का इस्तेमाल सजावट के साथ ही विभिन्न सजावटी आकृतियां बनाने में किया गया है। इससे चिड़ियाघर की खूबसूरती में चार चांद लगे हैं।

अब सोवेनियर बनाने की तैयारी

जू के निदेशक पात्रो के मुताबिक हमने प्लास्टिक कचरे को एक संसाधन के रूप में लिया है। इसके अच्छे नतीजों को देखते हुए अब प्लास्टिक बोतलों से सोवेनियर बनाने की तैयारी है। वह बताते हैं कि जू में सालभर में छह लाख से ज्यादा सैलानी आते हैं। सैलानियों द्वारा छोड़ी जाने वाली प्लास्टिक की बोतलों से सोवेनियर बनाए जाएंगे और यह कार्य महिला समूहों अथवा स्वयं सहायता समूहों को दिया जाएगा, ताकि रोजगार सृजन भी हो सके।

यह है थ्री आर पहल

रिड्यूस: जू में आने वाले सैलानी यदि अपने साथ प्लास्टिक की पानी की बोतल ले जाना चाहते हैं तो उनसे 10 रुपये जमा कराए जाते हैं। वापसी में खाली बोतल जमा कराने पर उन्हें यह राशि लौटा दी जाती है। यदि कोई ऐसा नहीं करता है राशि नहीं लौटाई जाती है। जू के भीतर छोड़ दी गई बोतल शाम को जू का स्टाफ एकत्र करता है। जो कर्मचारी जितनी खाली बोतलें लेकर आता है, उसे बदले में प्रति बोतल 10 रुपये दिए जाते हैं। इससे प्लास्टिक कचरे को एकत्र करने में मदद मिली।

रीसाइकिल: प्लास्टिक की बोतलों को रीसाइकिल करने के मद्देनजर जू में सालभर पहले पेट बोटल क्रशिंग मशीन लगाई गई। प्लास्टिक की खाली बोतलों को मशीन में डालकर चूरा तैयार कर लिया जाता है। फिर इसे 15 से 17 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है।

रीयूज: चिड़ियाघर में प्लास्टिक बोतलों के साथ ही पॉलीथिन, थर्मोकोल समेत अन्य अनुपयोगी सामग्री का उपयोग जू की खूबसूरती बढ़ाने में किया गया है। जू का सर्पबाड़ा हो कैक्टस गार्डन या फिर अन्य क्षेत्र, वहां प्लास्टिक की बोतलों से आकृतियां तैयार कर इन्हें सीमेंट के खाली कट्टों का जाल बनाकर ढका जाता है और फिर मजबूती के लिए सीमेंट की हल्की लेयर इन पर डाली जाती है। इसके बाद कलर किया जाता है।

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आवासीय परिसरों में खोलेगी सीएनजी पंप

नई दिल्ली। एजेंसी

सीएनजी पंपों पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करने के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) आवासीय परिसरों के अंदर

सीएनजी स्टेशन खोलने पर विचार कर रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक ई एस रंगनाथन ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि आईजीएल ई-वाहन चार्जिंग क्षेत्र में भी उतरने की सोच रही है। इसके लिए वह अपने सीएनजी पंपों पर चार्जिंग की सुविधा देगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सीएनजी और पाइप वाली प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करती है। कंपनी सीएनजी स्टेशनों पर गैस भरवाने के लिए लगने वाली कतार की समस्या से जूझ रही है। इसकी वजह से कई जगहों पर जाम जैसी स्थिति हो जाती है। उन्होंने कहा कि पायलट आधार पर नोएडा में एक आवासीय परिसर में सीएनजी वितरण पंप स्थापित किया गया है। अधिकारी ने कहा, 'हमें केवल 100 वर्गमीटर क्षेत्र की जरूरत है, जो कि चार कारों की पार्किंग के बराबर जगह होती है। हम सीएनजी पंप स्थापित करेंगे और उसमें कर्मचारी भी रखेंगे। आवासीय परिसर में रहने वालों को सीएनजी भरवाने में प्राथमिकता दी जाएगी। पंप को चलाने की जिम्मेदारी कंपनी की ही होगी। रंगनाथन ने कहा कि आईजीएल ई-वाहनों की चार्जिंग की सुविधा भी स्थापित कर रही है। इसके लिए उसने नीदरलैंड (डच) की एक कंपनी से गठजोड़ किया है। उन्होंने कहा कि आईजीएल की चालू वित्त वर्ष में 60 नए सीएनजी वितरण केंद्र खोलने और कम से कम दो लाख पाइप गैस कनेक्शन देने की भी योजना है। कंपनी अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए डीलर-फ्रंचाइजी प्रारूप को अपनाया है।

सोशल मीडिया पर शेयरों के बारे में अफवाह फैलाने वालों को पकड़ेगा सेबी

मुंबई। दलाल स्ट्रीट के जो सटोरिए अपने स्टॉक आइडिया को हवा देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, उन पर वार हो सकता है। नए नियमों के हिसाब से मार्केट रेगुलेटर सेबी लिस्टेड कंपनियों के बारे में ट्विटर और वॉट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरें उड़ाने वाले मार्केट पार्टिसिपेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। सेबी के प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर प्रैक्टिसेज (PFTUP) रूल्स के दायरे में अब तक सिर्फ प्रिंट मीडिया ऐड के जरिए दी जाने वाली झूठी जानकारी ही आती थी। रेगुलेटर ने इस रूल का दायरा बढ़ाकर डिजिटल मीडिया को भी इसके तहत ला दिया है। सेबी किसी भी एंटिटी के खिलाफ रेगुलेटरी एक्शन शुरू कर सकता है, अगर उसे लगे कि वह ट्विटर जैसे किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म या वॉट्सऐप जैसे ऐप पर मेसेज के जरिए किसी कंपनी के बारे अफवाह फैला रहा है। सेबी का नया रूल बाजार के मौजूदा माहौल को देखते हुए अहम हो जाता है जिसमें दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन (DHFL) और इंफीबीम एवेन्यूज सहित कई कंपनियों के स्टॉक्स तेज गिरावट की मार झेल चुके हैं।

मार्केट रेगुलेटर का यह कदम फेयर मार्केट एक्सेस को लेकर उसकी ओर से बनाई गई टी के विश्वनाथन कमेटी की सिफारिशों का हिस्सा है जिसे पिछली बोर्ड मीटिंग में स्वीकार किया गया था। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि बाजार में धोखाधड़ी करने वाले अफवाह फैलाने के लिए धड़ल्ले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इनकी बड़ी पहुंच होती है और इसमें अफवाह फैलाने वाला गुमनाम रह सकता है।

खेतान एंड कंपनी के पार्टनर सुधीर बस्सी ने कहा, 'सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह की अफवाहें तैरती रहती हैं, जो किसी प्रमोटर या स्टॉक को नुकसान पहुंचाने के लिए उड़ाई जाती हैं। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाह को फ्रॉड के दायरे में लाया जाना मौजूदा हालात के हिसाब से जरूरी कदम है क्योंकि सोशल मीडिया का असर पहले से काफी बढ़ गया है।' सोशल मीडिया पर अनैतिक और गैरकानूनी गतिविधियां बढ़ने की बड़ी वजह इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और रेगुलेटर के बीच किसी तरह का ठोस डेटा शेयरिंग सिस्टम नहीं होना भी है।

वॉट्सऐप पर कई ब्लूचिप कंपनियों के प्रॉफिट रिजल्ट लीक मामले की जांच में सेबी पहले से ही जुटा है। हालांकि वॉट्सऐप की तरफ से डेटा शेयरिंग में अनिच्छा दिखाए जाने से सेबी को अपनी जांच में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ साल पहले तक एसएमएस अफवाह फैलाने का सबसे पॉपुलर तरीका हुआ करता था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से 2014 में जारी आदेश से सेबी को जांच के दायरे में आने वाले किसी भी शख्स के कॉल डेटा रिकॉर्ड और मेसेज हिस्ट्री टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से मांगने की इजाजत मिल गई। उस ऑर्डर से टेलीकॉम प्रोवाइडर्स सेबी के साथ इनफॉर्मेशन शेयर करने पर मजबूर हो गए।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।